NOTES

Political History of India 1757to 1947

M A History (Sem 4th)

Paper Code 21His24gd1

Index

प्रश्न 1. भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक ढांचे के विकास का उल्लेख कीजिए

प्रश्न 2. वारेन हेस्टिंग की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए

प्रश्न 3.लॉर्ड कर्जन की प्रशासनिक नीति पर प्रकाश डालिए

प्रश्न 4. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ई पर एक निबंध लिखिए

प्रश्न 5. औपनिवेशिक राज्य के शस्त्र पर एक नोट लिखिए

प्रश्न6.भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए

प्रश्न7.भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए

प्रश्न 8.. भारतीय देसी राज्यों का विलय एक रक्तहीन क्रांति थी व्याख्या कीजिए.

प्रश्न 9. भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है

प्रश्न 910. भारत की विदेश नीति के निर्माणत्मक तत्वों की विवेचना कीजिए

प्रश्न 11. भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए

प्रश्न 12. गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक निबंध लिखिए

प्रश्न 1. भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक ढांचे के विकास का उल्लेख कीजिए

Ans भारत में राज्य स्थापित करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को एक उचित शासन प्रणाली लागू करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा 1757 से 1857 तक के इस 100 वर्षीय इतिहास में कंपनी की प्रशासनिक नीतियों में कुछ परिवर्तन आए परंतु भारत में शांति और सुरक्षा स्थापित कर कंपनी के व्यापार को उन्नत करना तथा अधिक लाभ उठाना यह उद्देश्य से सदैव कंपनी के समझ रहा अपने इन्हीं देशों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को दिशा निर्देश देने वाले विभिन्न अधिनियम पारित किए गए जिनका वर्णन इस प्रकार से है

1. **रेगुलेटिंग एक्ट 1773.** वारेन हेस्टिंग में 1773 इसी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करवा कर 1774 में लागू किया गया यह कानून का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना था

रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य धाराय.

1 कंपनी के डायरेक्टर की संख्या 24 की गई तथा 4 वर्ष के लिए चुने गए इनमें एक बटे चार को प्रत्येक वर्ष अवकाश लेना था डायरेक्टर को चुनने का अधिकार 500 पूर्ण की बजाय 1000 पूर्ण वार्षिक आय वालों को था

2. डायरेक्टर सैनिक में राजस्व संबंधी रिकार्ड प्रतिवर्ष ब्रिटिश खजाने में जमा कर आएंगे

3. बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तथा मुंबई में मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए

4. गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की एक काउंसिल पांच वर्ष के लिए बनी

5. गवर्नर जनरल में काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार दिए

6. गवर्नर जनरल अपना कार्य काउंसिल की बहुमत से करता.1793 का एक्ट. कंपनी को था मत बराबर हो तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार था

7. इस एक्ट द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश वह तीन अन्य न्यायाधीश थे

2 1773 एक्ट. इसी में 20 वर्षों का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था अतः 1793 में पुनः नया अधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी इसके द्वारा कंपनी की एक अधिकार तथा शक्ति को थोड़े बहुत संशोधन के साथ कौन है बढ़ा दिया गया

एक्ट की धाराएं

1. कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का 20 वर्ष के लिए एक अधिकार दिया गया

2. गवर्नर जनरल और गवर्नर अपनी जिम्मेदारी पर अपनी काउंसिलों की अपेक्षा कर सकते थे

3. नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को वेतन भारतीय कोर्ट से किया जाएगा

4. मुख्य सेनापति काउंसिल का सदस्य नहीं होगा जब तक संचालक को उसे विशेष रूप से सदस्य नियुक्त न करें

5.शराब बेचने के लिए प्रमाण पत्र का लेना आवश्यक बना दिया गया

6.पदोन्नति के मामले में नौकरी की अवधि को ही मापदंड बना दिया गया

7.कंपनी की कर्मचारियों द्वारा उपहार लेना सामान्य अपराध के बराबर बना दिया गया

8. एहस्तछेप की नीति का फिर से जोड़ दिया गया

3.1813 का एक्ट. गवर्नर ऑफ़ नेपोलियन युद्ध तथा मुक्त व्यापार की बढ़ती प्रसिद्ध के दौर में पारित किया गया था इन विचारों तथा घटना विकास का नतीजा यह निकला कि हिंदुस्तान की व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया लेकिन चीन के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा जहां तक प्रशासन के संबंध का सवाल है चार्ट के नियंत्रण मंडल का अधिकार दिया कि वह कंपनी के कर्मचारियों को नागरिक रासायनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है एक्ट में हिंदुस्तानियों के बीच शिक्षा

ज्ञान विषय में ₹ 100000 सालाना खर्च का प्रावधान दिया गया नेपाली का विचार था कि हिंदुस्तान का साम्राज्य संसद को सपना ठीक नहीं था क्योंकि हाउस ऑफ कॉमंस के पास में तो जरूरी समय है उन्हें ही जरूरी ज्ञान होने ही उसके पास वह ज्ञान पाने हेतु कोई लक्ष्य है जिससे कि हिंदुस्तान के मामले सुलझाए जा सके

धाराएं.

1. चार्ट 20 वर्ष के लिए फर्ला से लागू कर दिया गया

2. कंपनी को प्रादेशिक तथा व्यापारिक खाते को अलग-अलग रखने को कहा गया

3. गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ़ तथा मुख्य सेनापतियों के दफ्तर में नियुक्तियों के लिए सम्राट के लिखित स्वीकृति तथा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर उसे पर होना जरूरी बना दिया गया

4. नियंत्रण बोर्ड की देखरेख तथा आदेश के अधिकारों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई तथा उन अधिकारों में वृद्धि भी हो गई

5. चाय को छोड़कर बाकी चीजों के व्यापार करने की सम्राट की प्रजा को खुली छुट्टी मिल गई फिर भी चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी में अपने पास रखा

6. शांति के न्यायाधीशों का कार्य क्षेत्र अन ब्रिटिश प्राजजनों पर बढ़ा दिया गया जो भारत वासियों से मारपीट करें उनके घरों में अनाधिकार रूप से घुस जाए तथा जहां उनके खिलाफ भारतवासियों की पैसे ज्यादा के रन का मुकदमा हो

7. किसी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह इस बात का ठोस प्रमाण न दे कि उसने हिलवारी कॉलेज में शिक्षा के चार सत्र व्यतीत किए हैं और कॉलेज के सभी नियमों का भी पूरी तरह पालन किया है

8. भारतीय शिक्षा हेतु ₹ 100000 सालाना लगाना निश्चित किया गया

9. इसे अपने भारतीय राजस्व के प्रयोग को नियमित किया कंपनी के खर्चे में सबसे पहला स्थान फौजियों को देखभाल को दिया गया शुद्ध चुकाने को द्वितीय स्थान और नागरिक तथा व्यापारिक संस्थानों की देखभाल को तीसरा स्थान दिया गया

4.1833 का एक्ट. 1833 ई का ज्यादा अधिनियम संविधान के इतिहास में मुख्य स्थान रखता है इसलिए कंपनी का व्यापारिक संस्थान के रूप में अंत कर दिया मार्च में के अनुसार डायरेक्टर की बोर्ड की नीति में कुछ उत्थान आया और उनके प्रशासन में कुछ अधिक कार्य कुशलता ए कानून के क्षेत्र में एकरूपता स्थापित कर चार्ट ने विधि की अराजकता को बिल्कुल खत्म कर दिया उसने सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में

नर्सरी भेदभाव पर गहरी चोट की **1833** इसी में चार्ट ने इस मैच को खत्म नहीं किया कि कंपनी का शासन बना रहना चाहिए अथवा खत्म कर देना चाहिए इसके ठीक विपरीत एक्ट कितने कुछ नए सवालों को जन्म दिया कानून बनाने के लिए एक विशिष्ट संस्था व स्थानीय सरकारों को भागीदारी की जरूरत अनुभव की जाने लगी

धाराये.

1. हर प्रेसीडेंसी काउंसिल में एक गवर्नर और तीन के स्थान पर दो सदस्य कर दिए गए।

2. इसे अपनी गवर्नर जनरल बंगाल की उपाधि बदलकर गवर्नर जनरल भारत कर दी ली का अर्थ यह था कि इस वक्त की विचारधारा में केंद्रीय कारण की ओर है उसे मुंबई और मद्रास की प्रेगनेंसी पर और अधिक नियंत्रण दिया गया

3. ब्रिटिश यूरोपीय प्रजनन से भारत आने के लिए लाइसेंस लेने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया

4. इश्क ने सरकारी नौकरियां सबके लिए धर्म जन्म स्थान पैदाइश तथा रंग रूप के आधार पर बिना भेद रख खोल दे सरकारी नौकरी के लिए केवल योग्यता को ही आधार बनाया गया

5. कोलकाता मद्रास और मुंबई में विश्व की नियुक्ति करनी थी कोलकाता का विश्व की भारत की राजधानी का विशप होना था

5.**1853 का एक्ट .** इस चार्टर एक्ट में विधि सद्स्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया कथा यह व्यवस्था की की विधि निर्माण कार्य हेतु इस परिषद के साथ अन्य सदस्य भी शामिल हो इन छह सदस्यों में दो सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा चार सदस्य बंगाल मुंबई मद्रास और उत्तर पश्चिमी फ्रांस के प्रतिनिधि होते थे इन प्रतिनिधियों हेतु यह जरूरी था कि वह सैनिक कर्मचारी है वह कंपनी की सेवा का **10** वर्ष का अनुभव रखते हो **1853** ई का चार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए छात्रों की श्रृंखला में आखिरी था इस चार्ट ने एक प्रकार से हिंदुस्तान में आधुनिक विधायिका की ले रखी और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुनी गई इन कार्यों के महत्व को भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि **1853** की चार्ट में जरूर से ज्यादा केंद्रीय करें के दोस्त को दूर करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया सरकारी सेवा के द्वार अभी भी उनके लिए बंद रहे इसका चार्ट की आयु केवल **6** वर्ष रही

प्रश्न 2. वारेन हेस्टिंग की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए

Ans. ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी व्यापार करना और धन कमाना इसका मुख्य उद्देश्य था परंतु **18**वीं शताब्दी के मध्य में कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई धीरे-धीरे उसका राज्य विस्तार

हुआ यह देखना रोचक होगा कि कंपनी ने अपने नव विकसित प्रदेशों का किस प्रकार शासन प्रबंध चलाया होगा आरंभ में कंपनी ने शासन व्यवस्था भारतीय कर्मचारियों के हाथों में ही छोड़ी हुई थी परंतु उसे समय बाद कंपनी ने प्रशासन शासन प्रबंध को अपने हाथों में लेकर उसे पर नियंत्रण जमाया कारण हेस्टिंग्स और खंडवाज के समय में बंगाल तथा बिहार और में अंग्रेजी शासन प्रणाली की निम्नलिखित में कंपनी का प्रमुख उद्देश्य देश में शांति व सुरक्षा की स्थापना करना तथा अपने व्यापार को अधिक विकसित में उन्नत करना था कंपनी के शासन के आधार स्तंभ थे सिविल सर्विसेज सी और पुलिस

1. केंद्रीय प्रशासन.स्टूडियो कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ई को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के रॉयल चार्ट के माध्यम से की गई थी इस कंपनी का उपदेश मुख्य रूप से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था कंपनी के आरंभिक प्रबंध में एक गवर्नर एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य रखे गए थे जिनका काम कंपनी को सुचारू रूप से चलाना था शुरू में कंपनी के सदस्यों की नियुक्ति स्वयं महारानी एलिजाबेथ द्वारा की जाती थी परंतु आगे चलकर साधारण सदस्यों की नियुक्ति चुनाव के माध्यम से होने लगी थी कंपनी के इस प्रबंध को कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा इसके साधारण सदस्यों को डायरेक्टर्स कहा जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था उसमें कोई भी व्यक्ति 200 फोन की राशि जमा करवरकर कंपनी का सदस्य बन सकता था1765 ईस्वी में कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का रूप धारण कर लिया परंतु उसने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त नहीं किया कंपनी द्वारा बंगाल में दोहरा शासन लागू किया गया परंतु कंपनी के सदस्य व्यापारिक प्रवृत्ति के होने के कारण अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करने में कौन से असफल रहे इसके कारण बंगाल में व्यवस्था फैल गई इसलिए कंपनी पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया था इसके अतिरिक्त कंपनी के अधीन तीन प्रेसिडेंशियल बंगाल मद्रास मुंबई के गवर्नर जनरल का स्वतंत्र होने के कारण आपस में सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए कंपनी की प्रशासन विधि एवं परिवर्तन करना बहुत आवश्यक हो गया था अपरियन की सरकार ने अलग-अलग अधिनियम द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन में अधिक परिवर्तन कीजिए जिनका वर्णन इस प्रकार से है

1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 . ब्रिटिश सरकार द्वारा यह अधिनियम कंपनी पर कुछ अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को जनरल बनाया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर उनके अधीन कर दिए गए गवर्नर जनरल को युद्ध तथा संधि करने का भी अधिकार प्रदान किया गया भारत में कंपनी की सर्वोच्च शक्ति गवर्नर जनरल की ही था उसकी सहायता करने के लिए क्या सदस्यों के लिए काउंसिल बनाई गई जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया गवर्नर जनरल तथा

उनकी काउंसिल को निर्णायक मत देने का भी अधिकार दिया गया इस एक्ट के द्वारा भारतीय केंद्रीय सरकार की स्थापना की दिशा में पहला महत्वपूर्ण पार्क उठाया गया

2. पिट्स इंडिया एक्ट **1784.** रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए **1784** इसी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के दीवानी सैनिक मालगुजारी शासन पर नियंत्रण रखने के लिए **6** सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इसकी सदस्यों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या चार से घटकर तीन कर दी गई गवर्नर जनरल की शक्तियां में पहले से ज्यादा वृद्धि की गई जेसीबी काउंसिल के निर्णय को पलट सकता था मुंबई के समुद्र से गवर्नर पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए

3. 1793.ई का चार्टर एक्ट. इस अधिनियम के द्वारा यह फैसला किया गया कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की काउंसिल के सदस्य वही व्यक्ति बन सकते थे जिन्होंने कम से कम **12** वर्ष भारत में व्यतीत किया हूं वह प्रधान का एक नया पद बनाया गया जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में काउंसिल की अध्यक्षता करने का अधिकार रखता था प्रधान सेनापति को काउंसिल से बाहर निकाल दिया गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को अपनी-अपनी काउंसिलों के निर्णय को बदलने का अधिकार दिया गया

4. 1833 का चार्टर एक्ट. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा उसे समय भारत के वित्तीय सैनिक तथा अन्य सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई इस पर सर्वप्रथम लड़ में कल को नियुक्त किया गया

5. 1853 का चार्टर एक्ट. **1853** ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कंपनी दगयाि‍ए अंतिम चार्टर एक्ट पारित किया इसके द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भर से मुक्त कर दिया गया बंगाल का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर की अधीन कर दिया गया विधि सदस्य को कार्यपालिका परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया जिसका सदस्य संख्या **12** निश्चित की गई कानून बनाने का अधिकार भी इसे ही दिया गया कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी इसे दिया गया

2. प्रांतीय शासन

1. मद्रास. अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित तीन प्रेसीडेंसी में सबसे पहले प्रेसीडेंसी मद्रासी थी इसके प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी गवर्नर तथा उनकी काउंसिल को थी **1773** ई तथा **1784** ई के अधिनियम द्वारा

मद्रास के गवर्नर पर गवर्नर जनरल का कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया 1833 में चार्ट से मद्रास से कानून बनाने का अधिकार भी छीन लिया गया

2. बम्बई. अंग्रेजी साम्राज्य मुंबई एक महत्वपूर्ण प्रेसीडेंसी थी इसका शासन शुरू से ही गवर्नर तथा उनकी काउंसिल की अधीनता रखा गया था 1773 तथा सूत्र 84 ई के अधिनियम द्वारा एक प्रेसीडेंसी पर भी गवर्नर जनरल का खड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया था 1833 ई की चार्ट द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी से भी कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया

3. बंगाल. अंग्रेजों द्वारा स्थापित तीन प्रेसिडेंशियल में बंगाल सबसे महत्वपूर्ण थी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा यहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद से सुशोभित किया गया कारण हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंशियल को भी उनके अधीन रखा गया 1833 ई की चार्ट द्वारा इस प्रेसीडेंसी को शासन चलाने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल को सोफ दी गई

4. उत्तर पश्चिमी प्रांत. 1834 ई में ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत की स्थापना की गई इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया 1877 ईस्वी में इस अवधि में मिला दिया गया

5. सिंध. सिंधु को 1843 सीसी में ब्रेड साम्राज्य में लाया गया था आरंभ में यहां के शासन की जिम्मेदारी कमिश्नर को सौंप गई थी 1847 ईस्वी में इस प्रांत को मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ले लिया गया

6. पंजाब. पंजाब को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था शुरू में इसके शासन की जिम्मेदारी तीन सदस्यों के प्रशासनिक बोर्ड को जीवित सौंप दी गई 1853 में ई तक पंजाब इसी के अधीन रहा 18530 में इसके शासन को चलाने की जिम्मेदारी के कमिश्नर को शांति गई

7. अवध. अवध को 1856.में ब्रिटिश साम्राज्य शामिल किया गया था इसके शासन की जिम्मेदारी के चीफ कमिश्नर को सोफ की गई

प्रश्न 3.लॉर्ड कर्जन की प्रशासनिक नीति पर प्रकाश डालिए

Ans. कर्जन के आंतरिक सुधार . लॉर्ड कर्जन ने अंतरिक्ष सुधार करने का भर्षक प्रयास किया प्रत्येक क्षेत्र में उसने सुधार कार्यक्रम लागू किया वायसराय में प्रत्येक भाग से कहा कि वह अपनी उद्देश्य को स्पष्ट विवेचना करें भविष्य में विकास की विधि पर विचार करें तथा यह निर्धारित करें कि कौन से साधनों को अपनाना सहिष्कर होगा इस प्रकार से मूलभूत प्रश्नों पर विचार करके आगे बढ़ाने की योजना ही बनाई गई

1. **प्रशासनिक मशीन की मरम्मत.** वायसराय ने शुरू से ही यह निर्णय कर लिया था कि प्रशासनिक ढांचे को अधिक कारगर ढंग से चलने की योग बनाया है देगा इसके लिए यह आवश्यक था कि केंद्रीय सरकार के

कार्यालय के काम करने की प्रणाली पर पुनर्विचार हो गवर्नर जनरल बनते ही उसने प्रत्येक विभाग की कार्य विधि की परख ली उसने देखा कि कार्यालय के काम में बहुत अधिक विलंब होता था जिसे दूर करना जरूरी था उदाहरण के लिए करनाल को पदोन्नति करने की प्रश्न पर 15 महीने पर तक विचार होता रहा था और जब यह प्रश्न वायसराय के विचार में के लिए पहुंचा तो उनके पूर्व छपे हुए 53 पन्ने भरे जा चुके थे कार्यालय में होने वाली देरी का एक कारण था की यह नियम बना हुआ था कि प्रत्येक प्रमुख मसले पर नोट किस सिलसिले से पेश किया जाए अच्छा अधिकारी वही माना जाता था जो इस नोट लिखने के कार्य में दक्षता दिखाएं

उसके शासन के बारे में कहा जाता है कि केंद्रीकरण के सिद्धांत का पशुपति था लेकिन यदि हम उसके वक्तव्य और कार्यों का शुभ दृष्टि डालें तो यह देखेंगे कि वायसराय मद्रास और मुंबई के गवर्नर की विशेष स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई अन्य प्रति के लेफ्टिनेंट गवर्नरों की तुलना में हिंदू प्रति के गवर्नर की नियुक्ति दूसरे ढंग से होती थी तथा यह गवर्नर ग्रह सरकार से संपर्क भी कर सकते थे इसे केंद्रीय सरकार के लिए समस्याएं उत्पन्न होती थी यदि कर्जन ने हिंदू कॉर्नर की विशेष स्थिति को समाप्त करके उनके अधिकारों को अन्य क्रांति के गवर्नर के समान करना चाहा तो उसके लिए उनकी आलोचना करना उचित नहीं होगा

2. **आर्थिक सुधार**. आर्थिक सुधारो की ओर कर्जन में पर्याप्त ध्यान दिया उसकी इन सुधारो को तीन भागों में बांटा जा सकता है

A. **काल का मुकाबला करने केदिखाई.** लॉर्ड कर्जन को जी शक्ल का सामना करना पड़ा उसके विषय में एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि पिछले 200 वर्षों में भारत में जो काल पड़े थे उनमें से सबसे अधिक स्त्री तथा सबसे अधिक व्यापक था इसी से साफ जाहिर होता है कि वायसराय को 1899 ई के भीष्म काल से किस प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा देश की आर्थिक स्थिति इस कारण और भी बिगड़ गई 1899 और 1900 ईस्वी में जो काल पड़े उनका प्रभाव करीब 2 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में पड़ा था ब्रिटिश भारत के आने वाले क्षेत्र के लगभग 2000000 लोगों पर इसका असर पड़ा मध्य प्रदेश बर मुंबई अजमेर मारवाड़ भी अकल की कठिनाइयों से त्रस्त थी इसकी अतिरिक्त पंजाब मद्रास बंगाल आदि क्षेत्रों में भी अनाज की कठिनाई या उत्पन्न हुई यह अनुमान लगाया गया की 70 करोड रुपए मूल्य की फसल नष्ट हो गई थी क्रांति सरकारों ने काल पीढ़ी क्षेत्र में राहत पहुंचाने प्रारंभ में कुछ नई भर्ती विश्व जनता की कठिनाई और अधिक बड़ी परंतु इसके बाद विभिन्न रहाटकर आरंभ करके प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को सहायता देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गईइतने अधिक लोग भूख से मर गए की सरकार को फ्री

अलसी का सामना करना पड़ा सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत की उनके अनुसार लगभग 20 लाख लोग काल से मारे लेकिन गैर सरकारी अनुमान यह था कि यह संख्या इससे अधिक कहीं अधिक थी अर्जुन की कार्यकाल नहीं प्रकाशित एक प्रसिद्ध पुस्तक लेकर लेखक के विलियम डिग्गी नगर कल से करने वाले लोगों की संख्या 32 लाख से कुछ अधिक ही आगे है राष्ट्रीय नेताओं ने 20वीं शताब्दी के वर्षों की कट वाले चालाकी नानी आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां दोष कौन थी इनके कारण ऐसे भयंकर अकाल पड़े थे कर्जन की सरकार भी चुप नहीं थी बैठ सकती थी और उसने प्रतिवाद में बहुत कुछ कहा परंतु उसकी भी अधिक महत्वपूर्ण यह वह थी कि सरकार के रुख में एक बड़ा परीक्षण आया 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक प्राय यह कहा जाता था की काल रोकथाम करने के उपाय करना सरकार का काम नहीं था क्योंकि भारतीय खेती मानसून की वर्षा पर आधारित थी और वर्ष में होने पर काल की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती थी लेकिन अब सरकार ने अपना उत्तरदायित्व समझा और ऐसे उपाय ऊपर विचार किया जिससे वर्षों न होने पर भी अकल की स्थिति का मुकाबला किया जा सके

B. **कृषि में सुधार.** भारत सरकार ने अभी तक केवल लगान वसूल करने का ही ध्यान रखा था लेकिन कृषि की दशा सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया इसलिए कुछ दशक में और प्रयास आरंभ हो गई थी और कर्जन ने पहली बार कृषि सुधार के उपाय पर गंभीरता से विचार किया तथा उपयोगी कार्यक्रम लागू की है उसने जो कृषि नीति अपना उसके आधारभूत सिद्धांत थे प्रयोग अनुसंधान और शिक्षा 1901 ईस्वी में कृषि का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया और सरकार ने अन्य कृषि विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी थी कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पुणे में एक इंस्टिट्यूट खोला गया इस स्थापना करके कर्जन ने भारतीय कृषि की समस्याओं का अध्ययन करने का वैज्ञानिक आधार तैयार किया कृषि शिक्षा के लिए कॉलेजों को प्रभावशाली बनाय।

C. **भूमिकर से संबंधित समस्याएं.** काल से संबंधित तथ्यों पर विचार करने से एक वह तथ्य सामने आया था कि इसका सबसे अधिक प्रभाव किसने पर पड़ता था 19वीं शताब्दी के समाप्त होने पर यह देखा गया कि किसानों की आर्थिक दशा बड़ी ही सोच रही थी पैदावार जब अच्छी होती थी तो वह किसी प्रकार जीवन निर्वाह कर लेता था पर फिर भी उसके पास अथवा धन की बचत नहीं हो पाती थी यह बचत इसलिए जरूरी थी कि उसका उपयोग हुआ तब कर सकता था जब सुख अथवा कल की करती हो लेकिन भारतीय किसान इतना अधिक गरीब या तथा कर्ज से इस हद तक ढाबा रहता था कि हैदराबाद में होने पर उसके पास खुद जमा नहीं होता था और फलक से अकल का आरंभ होते ही उसे भुखमरी का सामना करना पड़ता था राष्ट्रीय नेताओं ने जोरदार शब्दों में ऐसी स्थिति का चित्रण किया और सरकार से मांग की कि वह लगान वसूल

करने के नियमों पर पुनर्विचार करें तथा किसानों को राहत पहुंचाने की अनुपम करें लार्ड कर्जन ने इस और सराहनीय कार्य किया

करजानी मार्च **1905** ईस्वी में नियम बनाए जिनमें अनुसार लगान वसूल करने में लक्ष्मी फल का सिद्धांत अपनाया गया स्थानीय अधिकारी यह निश्चित कर सकता था कि किस समय में लगन को वसूली स्थगित कर दे **1901** ईस्वी में कर्जन ने एक अधिनियम पारित करके यह व्यवस्था की की सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किस की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता था सबसे पहले इस नियम को पंजाब में लागू किया गया अभी तक कर शीला दे किसने की भूमि पर शुद्ध कोर जब चाहे कब्जा कर लेते थे इस प्रकार से किसानों के हाथ से निकलकर भूमि व्यापारियों के हाथ में आज रही थी कर्जन ने पंजाब के किसानों की रक्षा की बात नहीं यह नियम अन्य प्रति में भी लागू किया गया शुद्ध खोरी से मुक्ति के लिए किस की रक्षा करना एक आवश्यक कदम था परंतु इसके अलावा सरकार की यह एक व्यवस्था भी करनी पड़ी की आसान शर्तों पर किस को धन दिलाया जाए वायसराय ने इस देश की प्राप्ति के लिए सरकारी समितियां की स्थापना की जो किसानों को आसान शर्तों पर धन देने लगी किसने की यह अवसर पहली बार मिला कि वे व्यापारियों की अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से कर्ज ले सकते थे

3. **रेलवे संगठन तथा व्यवस्था में सुधार.**भारत में रेल प्रशासन के संबंध में लोगों अपना विचार प्रकट किया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार करने का श्रेणी कर्जन को देना चाहिए रेलवे के विकास के करीब **50** वर्ष हो चुके थे इससे कई ऐसे सवाल विचाराधीन थी जिनके संबंध में किसी ने किसी प्रकार का निर्णय करने की जरूरत थी कर्जन ने इस उत्तरदायित्व को अपने कर्मों पर लिया और विवेक के विकास की नीतियां निर्धारित की भारत में रेलवे का व्यापक महत्व रहा उसे समय लंबी दूरी तक जाने आने का यही एकमात्र साधन था जिस प्रकार का कर्जन का तरीका था उसके तहत सबसे पहले ब्रिटेन से एक विशेषज्ञ थॉमस रॉबर्टसन को घर बुलाकर रेलवे से संबंधित सभी प्रश्नों पर अपनी राय देने को कहा **18** महीने तक विचार करने के बाद **1930** में रॉबर्टसन की रिपोर्ट कर्जन को प्राप्त हो गई इस रिपोर्ट में रेलवे के तत्कालीन ढांचे और उसकी कार्यप्रणाली की कटी वर्ष ना कीजिए बदलने के सुझाव दिए गए कर्जन को इससे किसी प्रकार का अक्षर नहीं हुआ क्योंकि उसका पहले से ही यह अनुमान था कि रेल प्रशासन तूतिपूर्ण थाकर्ज ने रेलवे के ढांचे में है सबसे पहले मुख्य परिवर्तन यह किया कि रेलवे को सार्वजनिक निर्माण विभाग के हास्य हटाकर उसका नियंत्रण **30** सदस्यों के एक स्वतंत्र बोर्ड को सौंप दिया इस नवगठित रेलवे बोर्ड को रेल प्रशासन की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई करजानी उद्योग और व्यापार के एक नए विभाग की स्थापना की जिसकी देखरेख में रेलवे बोर्ड काम करने लगा अभी तक रेल निर्माण के कार्य के विषय में भी स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई

थी कर्ज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में रेलवे लाइनों के निर्माण में सरकार का पूरा नियंत्रण रहे और व्यापारिक कंपनियों को केवल न्यायालय बढ़ा देने का कार्यक्रम आ जाए कर्जन की इस समय में जितने अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई उतनी किसी अन्य वायसराय के समय में नहीं बनी 60 करोड रुपए की लागत से उसने करीब 6000 मिल से कुछ अधिक लंबी रेल ने अपने समय में लगवाई

4. **पुलिस विभाग.** पुलिस के महत्व को प्रारंभ से ही कर्जन में समझा था इस विषय में उसे लिखा था कि पुलिस को सुधारना एक बड़ा प्रश्न था जिस पर सारी पर विश्वास की व्यवस्था आधारित थी विभिन्न प्रकार की पुलिस में सहयोग की कमी थी करजानी इन सभी प्रश्न संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए कमीशन 1902 में नियुक्त किया इस कमीशन की व्यवस्था और न्यू फीचर ने की लगभग 8 महीने के परिश्रम के बाद इसकी रिपोर्ट वास को पेश की गईइस रिपोर्ट के तत्कालीन पुलिस की कार्य प्रणाली की प्रति आलोचना की गई रिपोर्ट को प्रकाशित करने के बाद कमीशन की सुझाव पर कमल करना आरंभ हो गया और यह प्रक्रिया कर्जन के शासन के समाप्त होने के बाद भी जारी रही सबसे पहले प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई इससे सरकार का पुलिस पर होने वाला खर्च बढ़ा जब कर्जन आया था तो यह खर्च 21 लाख 17 हजार फोन प्रतिवर्ष था और उस के जाने के समय तक यह खर्च बढ़कर 32 लाख 12189 पॉइंट तक हो गया था इसे स्पष्ट होता है कि वायसराय में पुलिस को अच्छा वेतन देने की कोशिश की दूसरा सुधार यह किया गया कि पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई पहले कुल मिलाकर 149000 अधिकारी और पुलिस के जवान कार्य करते थे जिनकी संख्या बढ़कर 10071758 कर दी गई सशस्त्र पुलिस के संगठन को शक्तिशाली बनाया गया क्योंकि उसे समय की सेनापति कितना आभूषण था कि किसी बाहरी आक्रमण उसका युद्ध के समय इस पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सकता था इस नई नीति के अनुसार पुलिस को अच्छे प्रकाश की बंदूकन का इस्तेमाल करना सिखाया गया कर्जन नेवी महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अलग से उसके विभाग संगठित किया जाए भविष्य में इस विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी

5. **प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा.** भारत के ऐतिहासिक स्मारकों की तरफ ध्यान देने वाला कर्जन प्रथम वायसराय था उसने इस्मारकों की सुरक्षा करने का निश्चय किया अभी तक सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी उसकी उपेक्षा का प्रभाव यह पड़ा की इन भवनों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी वैसे को इससे संभव हुआ कि भारतीय में तो इन दोनों के विषय में कुछ जानते थे उन्हें उनकी सुरक्षा की उन्हें किसी प्रकार की चिंता थी जनता की अरुचि के कारण सड़क सरकार के लिए यह और भी जरूरी हो गया था कि कोई विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा करती अर्जुन ने जब एक बार

मद्रास की सरकार को लिखा कि वह पुरातत्व विविध से इन भवनों और अवशेषों के विषय में सलाह ले तो वायसराय को उत्तर मिला कि मथुरा सरकार ने कभी ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति में नहीं की थी कर्जन ने इस स्थिति को सुधार विभिन्न प्रांतो में पुरातत्व विभाग बनाया गया और पुराता टीवी विभाग के डायरेक्टर के पद पर प्रसिद्ध पूरा कर विद जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया 1904 ईस्वी में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित करके किसी भी ऐतिहासिक भूगोल को सुरक्षित स्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया आगरा और अजंता के भावनाओं की सुरक्षा में कर्जन में व्यक्तिगत तिरुचि दिखाई

6. **कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम .** किस अधिनियम द्वारा कोलकाता कॉरपोरेशन के आकार को घटा दिया गया इस कॉर्पोरेशन में अभी तक ड्यूटी हाय ऐसे सदस्य थे जिन्हें नगर के करदाता सुनते थे कदम के समय जो एक पारित किया गया उसमें ऐसे चुने गए सदस्यों का अनुपात घटा दिया गया अब केवल आधे सदस्य का जल प्रतिनिधि हो सकते थे प्रोसेस आदि सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया इस से कोलकाता को कॉर्पोरेशन में सरकार का प्रभाव बाद यह व्यवस्था भी की गई की कॉरपोरेशन की अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करें और इस अधिकारी को हर प्रकार की स्थिति में कई विशेष अधिकार प्रदान किए गए कॉरपोरेशन का केवल यह काम रह गया कि वह कर निर्धारित करें और नीति संबंधी सामान्य निर्णय करें एक समिति का भी संगठन किया गया जिसके 12 सदस्य थे सरकार ने इस अधिनियम द्वारा जल प्रतिनिधियों के अधिकारों को घटते समय तर्क दिया कि कारपोरेशन के सदस्य केवल बहस करते रहते थे परंतु हुई वास्तविक काम करने में रुचि नहीं लेते थे और इस नीति का आदेश अन्य भागों के साथ बंगाल में भी विरोध किया गया बंगाल की धारा सभा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस अधिनियम की वर्षण करते हुए कहा था कि जिस दिन यह अधिनियमपारित किया गया उसे बंगाल की भाभी पीढ़ियां उसे दिन के रूप में स्मरण रखेंगे जब कोलकाता में स्थानीय स्वशासन स्वायत शासन का उन्मूलन कर दिया गया कॉरपोरेशन की 28 भारतीय सदस्यों ने रोज़ प्रकट करने के लिए अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया 1923 ईस्वी में कर्जन के समय का अधिनियम संशोधित कर दिया गया और 80% सदस्यों की चुने जाने की व्यवस्था की गई सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही इस संशोधन को पेश किया था

प्रश्न 4. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ई पर एक निबंध लिखिए

Ans. शासक वर्ग में शासित वर्ग में वास्तविक संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य सरकार ने 1861 ई का भारतीय परिषद अधिनियम पास किया भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कदम था इस अधिनियम द्वारा सरकार ने भारतीय जनता के साथ सहयोग की नीति का श्री गणेश किया इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को शासन में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया

अधिनियम के पारित होने के कारण

1861 के अधिनियम की पारित होने के निम्नलिखित कारण थे

1. अंग्रेज सरकार की नीति में परिवर्तन. 1857 ई की क्रांति के पश्चात अंग्रेजी सरकार में महसूस किया कि भारतीयों के सहयोग के बिना भारत में लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है सर बटन गैर के शब्दों में मेरे विचार में भारतीयों का परिषद में लिया जाना आवश्यक हो गया क्योंकि जानने के लिए की भारतीय हमारे कानून के विषय में क्या सोचते हैं और उनका भारतीय समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे जानने के अवसर बहुत कम हो गए थे

2. स्वामी भक्त भारतीयों की मांग. अंग्रेजी सरकार के प्रति स्वामी भक्ति रखने वाले भारतीयों ने भी भारतीयों को कानून बनाने वाली संस्थाओं में स्थान देने की मांग की सर शायद अहमद खान ने एक बार कहा था कि यदि विधायिका परिषद में एक भी भारतीय होता तो भारतवासी विद्रोह करने की गलती नहीं करते जनता के पास सरकार तक अपनी आवाज और जाने का कोई भी साधन नहीं था इसलिए भारतीयों ने अंग्रेज़ सरकार सेवन की थी कि शासन में स्वदेशियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए ताकि शासन व शासित के बीच की दूरी कम की जाए

3. 1853 के अधिनियम के दोष. 1853 ईस्वी में चार्ट से कानून बनाने की व्यवस्था क्या केंद्रीकरण कर दिया गया था सारे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधान परिषद को ही था सभी छोटे-बड़े कानून वही बनते थे परंतु इस परिषद को देश के विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान जाम आना संभव नहीं था

4. परिषद में दोष. तत्कालीन विधान परिषद का संगठन भी संतोषजनक नहीं था समुचित देश के लिए कानून बनाने के लिए केवल एक ही परिषद थी इंग्लैंड जैसे एकात्मक राज्य के लिए इस प्रकार की परिषद का होना उचित था परंतु भारत जैसे व्यापक विभिन्नताओं वाले राष्ट्र के लिए यह अनुपयुक्त एवं का पर्याप्त था वर्तमान परिषद के गठन एवं कार्य विधि में सुधार करने का अंग्रेज सरकार ने निश्चय कर दिया था

5. प्रांतीय सरकारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना. शांति सरकारों को विधायिका परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था अत उनके चित्रों के लिए बनाए गए कानून में उनका कोई हाथ नहीं होता था यदि 1853 ई के चार्टर एक्ट में इस कवि को पूरा करने का प्रयास किया गया था परंतु यह पर्याप्त नहीं था अत उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना आवश्यक था

6. गवर्नर जनरल की असीमित अधिकार वर्तमान विधायक का के गवर्नर जनरल को अवीनियमित प्रान्तों के लिए कानून बनाने का अधिकार था इस संगठन त्रुटि को दूर करना आवश्यक था

7. भारतीयों की इच्छा पूर्ति के लिए. भारतीयों की शान में सुधार करने की मांग दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी भारतीय जनता काफी समय से शासन भाग लेने की मांग कर रही थी अतः भारतीयों की इच्छा को पूरा करने के लिए अधिनियम पारित करना आवश्यक हो गया था

अधिनियम की मुख्य धाराएं.

1. इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया इसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर पांच कर दी गई इसके अतिरिक्त सदस्य के लिए वित्त संबंधी ज्ञान आवश्यक था प्रधान सेनापति को पहले की भांति काउंसिल का असाधारण सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई

2. कार्यपालिका की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए गवर्नर जनरल को नियम व उप नियम बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्यों में कार्य वितरण करने का अधिकार दिया गया

3. गवर्नर जनरल को कानून बनाने में सहयोग करने के लिए अपनी काउंसिल में 6 से 12 तक सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया इनमें से कम से कम आदेश सदस्य गैर सरकारी रखे गए तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया

4. विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी इसके पश्चात ही वह विवेक ब्रिटिश भारत के समस्त क्षेत्र में लागू होता था

5. इस अधिनियम द्वारा प्रति की सीमाओं के परिवर्तन करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दिया गया था

अधिनियम के दोष.

1. अनिर्वाचित गैर सरकारी सदस्य. इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी नामांकित भारतीय सदस्यों को देश के लिए कानून बनाने वाली विधायिका में लिया गया था जो एक प्रगतिशील कदम था परंतु यह लोग जनता के प्रतिनिधियों की अपेक्षा उन्हें मनोनीत करवाने वाली प्रतिक्रिया आबादी शक्तियों के हितों के लिए काम करते थे मनोनीत किए जाने वाले अधिकांश सदस्यों में देसी नरेश जमीदार बड़े पूंजीपति तथा अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारी होते थे

2. नाममात्र की विधायिका सभाएं. इस अधिनियम के द्वारा बनने वाली विधानसभाओं केवल नाम मात्र के लिए ही कानून बनाने वाली संस्थाएं थी यह विधायिका ना हो का केवल उसकी एक समिति मात्रा थी उनकी विधायिका शक्ति अत्यंत समिति इन्हें प्रस्ताव पेश करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था

3. गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि. **1861** ई के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था इसे प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान मंडलों द्वारा पास किए गए विधायकों को वीटो करने का अधिकार दिया गया था

4. भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं. इस अधिनियम से भारतीयों की को विधान परिषद में वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला था क्योंकि सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर को तथा वह ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना था जो ब्रिटिश सरकार के भक्त थे

डॉक्टर एस आर शर्मा ने लिखा है कि सरकार का यह विचार नहीं था कि वह कानून निर्माण में कोई कारगर अगले यह तो कानून निर्माण की प्रक्रिया के साक्षी कार्य ही थे

प्रश्न 5. औपनिवेशिक राज्य के शस्त्र पर एक नोट लिखिए

Ans. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना शक्ति के बल पर की गई थी इसलिए उन्होंने **1857** ई तक मुख्य रूप से शक्ति के बल पर ही अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की सुरक्षा की थी कंपनी के शासन के आधार स्तंभ सिविल सर्विस सेवा और पुलिस की थी भारत में अंग्रेजी राज्य के पोषण तथा विस्तार में सिविल सर्विसेज का मुख्य योगदान है किसी ब्रिटिश साम्राज्य का फौलादी चौखट कहा जाता था सुना और पुलिस इसकी सहायक भूमिका में थे

1. नागरिक सेवा. ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक कल में लोक सेवा को विकास मुख्य विशेषता मानी जा सकती है इसका हिंदुस्तान में लोकसभा की परंपरा से प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार संबंध नहीं था कंपनी की लोक सेवा के विकास में कार्निवेश का उल्लेखनीय योगदान है उसने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर बिल्कुल रोक लगा दी तथा उपहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया इसके आवाज में कर्मचारियों का वेतन काफी बढ़ा दिया गया चार्टर एक्ट **1797** ने यह भी व्यवस्था की गई की लोक सेवा में नियुक्ति सामान्य हिंदुस्तान में कार्यरत कर्मचारियों में से ही की जाएगीव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है थी कि भारतीयों की योग्यता में चरित्र में विश्वास रखते हुए उसने लोक सेवा का पूर्ण रूप से यूरोपीयकरण कर दिया जिससे प्रशासनिक खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई इसके स्थान पर हर को में **1805** ईस्ट इंडिया का कॉलेज की हिंदी डेरी में स्थानांतरित कर दिया गया प्रशिक्षण केदो के निर्माण के बाद भी लोकसभा की एक बड़ी कमी बनी रही लोक सेवा का चयन अभी डायरेक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता था

2. सेना और पुलिस. सी अंग्रेजी सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी सी द्वारा भारतीय प्रति को जीत गया था सेनाही विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा का कार्य करती थी कंपनी की सेवा में अधिकांश भारतीय सैनिक ही थे इन्होंने ही कंपनी के लिए भारत को जीता था उसे समय भारत में एकता और राष्ट्रीय का भाव था बंगाल बिहार के सैनिक कंपनी के लिए पंजाब या महाराष्ट्र को जीतने में कोई असाधारण बाद में समझते थे वह अपने स्वामी के प्रति वफादार थे जो उसे वेतन देता था 1857 में कंपनी की सेवा की कुल संख्या 3 लाख 11400 थी जिसमें 265900 भारतीय ही थे सेवा में ऊंचे पर अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे

लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में पुलिस व्यवस्था का भी संस्थापक था उसने जमीदारों से पुलिस अधिकार छीन कर एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की प्रत्येक जिले में एक पुलिस कप्तान की नियुक्ति की जिलों को अनेक स्थानों में विभाजित किया गया प्रत्येक थाने में एक दरोगा का पद बनाया गया दारोगा पद पर भारतीयों को ही नियुक्त किया जाता था पुलिस विभाग भी भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था पुलिस देश में शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए उत्तरदाई थीपुलिस के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने डकैती तथा अन्य बड़े अपराधों पर काबू कर दिया था इसी प्रकार ठाकुरों का जो मध्य भारत में यात्रियों को लूट लेते थे दमन किया गया

3. न्याय प्रशासन. वारेन हेस्टिंग्स और कार्नवालिस नहीं भारत में नहीं न्याय व्यवस्था की आधारशिला रखी वाराणसी में जिलों को अंग्रेजी शासन प्रबंध का आधार मानकर कार्य किया प्रत्येक जिले में कलेक्टर की वेबसाइट में दिवाली अदालत की स्थापना की गई कलेक्टर भूमिका वाले की अतिरिक्त दीवानी मुकदमों का फैसला करने का कार्य भी करता था बाद में कार्नवालिस ने इसे न्याय संबंधी काम ले लिया प्रत्येक जिले में जिला अदालत के अतिरिक्त कुछ छोटे न्यायालय भी स्थापित किए गए एक छोटे न्यायालय में प्राय भारतीय जज जो मुंशी और अमीन कहलाते थे कार्य करते थे जिलों के न्यायालय से अपील सुनने के लिए चार प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए उन सबके ऊपर कोलकाता में एक सदर दीवानी अदालत थी फौजदारी मुकदमों की निर्णय करने के लिए दूसरी न्यायालय की स्थापना की गई

4. कानून का शासन.अंग्रेजों ने ही भारत को एक नई कानून व्यवस्था प्रदान की भारत में पराजय परंपरागत कानून तथा धार्मिक ग्रंथो पर आधारित कानून ही प्रचलित थे अंग्रेजो ने भारत के कानून का आदर करते हुए नए कानून भी लागू किया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्रदान की गई फिर कानून का संग्रह किया गया तथा भारतीय दंड संहिता में अन्य संहिताओं का निर्माण किया गया अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण दिन है कानून के शासन को लागू करना इससे भी प्राय है कि

शासन का कार्य किसी एक शासन की व्यक्तिगत इच्छा या भावना द्वारा में चलकर नियमित कानून और अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था कानून का शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक था अंग्रेजी कॉलोनी व्यवस्था की दृष्टि से सभी नागरिक कानून के समक्ष समान थी बिन धर्म और जातियों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू होता था अंग्रेजों से पहले भारतीय न्याय व्यवस्था में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण को ब्राह्मण के मुकाबले इस अपराध के लिए काम दंड दिया जाता था इसी प्रकार बड़े जमींदार और सामंत भी आम नागरिकों के मुकाबले में काम दंड आते थे परंतु अंग्रेजी में अर्थव्यवस्था की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान थी

निष्कर्ष. कानून के शासन में भारत के सभी वर्गों तथा जातियों को समान कर दिया परंतु यहां रहने वाले अंग्रेज लोग इससे अछूते थे अंग्रेज नागरिकों के लिए प्राय कृषक न्यायालय होते थे तथा अंग्रेजी कानूनी को ही ऊपर लागू किया जाता था अंग्रेजी सी सिविल सर्विस पुलिस अंग्रेजी कानून व्यवस्था कानून का शासन तथा कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत अंग्रेजी साम्राज्य के प्रशासन रूपी वह तंत्र थे जो अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा में सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं

प्रश्न 6. **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए**

Ans. भारतीय संविधान का निर्माण करना एक जटिल कार्य था इस कार्य को करने के लिए निर्माता को अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने अपनी समितियां की सहायता स्वीकार करना पसंद किया समितियां मुख्यतः प्रक्रियात्मक और विशिष्ट विषयों पर बनाई गई थी इन समितियां में सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रारंभ समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थी इस समिति के अन्य सदस्य थे और गोपाल स्वामी अय्यर मोहम्मद सादुल्लाह बी मित्र पुष्प में पश्चात उनके स्थान और राघव रानी प्राप्त किया था डीपी खेतान की जगह पर बाद में टीटी कृष्ण आचार्य आ गए

संविधान सभा में विधि जगत का राजनीतिक जगत के ऊपर आधिपत्य बना रहा सदन के सामने प्रारूप समिति के उपस्थिति की व्याख्या करने में डॉक्टर अंबेडकर ने एक महान संविधान शास्त्री की भूमिका निभाई

प्रारूप समिति की स्थिति इस नहीं मौका पर उसके बदलते हुए संकल्प विरोध के सूत्र बन गए यह सच है कि कुछ सदस्यों को प्रारूप समिति का अधिनायक वादी रुक जैसा कि इसके अध्यक्ष के व्यवहार में प्रतिबिंबित हुआ अप्रैल का परंतु जिसने उन्हें अधिक दुष्ट किया वह यह था कि प्रारूप धाराओं की व्यवस्थित ढंग से विवाद के लिए दिया गया और दूसरे सदस्य वचन कल में मूल्यांकन बदल दिया गया

भारतीय संविधान महान आदर्श पर आधारित है जिनका कांग्रेस दल ने सदैव बड़ी निष्ठा के साथ पालन किया और उन्हीं के लिए उन्हें संविधान धाराओं को औपचारिक रूप देने में लगभग 40 महीना का समय लगाया संविधान सभा ने कांग्रेस दल द्वारा स्वीकृत महान आदर्श को संविधान के शरीर में इस प्रकार अंगीकृत किया कि उसके आधारभूत सामाजिक दर्शन के अनोखे रूप का सृजन हुआ जो गांधी जी के धार्मिक अराजकतावाद के लोकतांत्रिक समाजवाद के अनोखे संगम में देखा जा सकता है

गांधीवाद के आधारभूत तत्व जैसे श्रीश्यता का अंत तथा धर्म प्रजाति आदि के आधार पर कृत्रिम भेदभाव के निराकरण को संविधान के न्याय मान्य भाग में रखा गया परंतु गांधीवादी अर्थशास्त्र राजनीति की अनेक सिद्धांतों जैसे ग्राम पंचायत का संगठन घरेलू उद्योग धंधों का विकास मध्य निषेध गोवत पर प्रतिबंध इत्यादि को संविधान के विकल्प द्वारा न्याय अमान्य भाग में रखा गया जिसका विवरण राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है

नेहरू की बुद्धिमत्ता पूर्ण विचारधारा का प्रभाव हुआ एक मौके पर उन्होंने यह कहा कोई संविधान यदि यह लोगों के जीवन उद्देश्यों में आकांक्षाओं से अलग है तो अपेक्षाकृत खोखला हो जाता है यदि वह उन उद्देश्यों से पीछे रह जाए तो लोगों को नीचे गिरा देता है उसे कुछ ऊंचा होना चाहिए जो लोगों की आंखों और मस्तिष्क को उच्च स्तर पर रख सके

हमारे संविधान की सबसे मुख्य को की विशेषता केवल उन पांच उपयुक्त स्वीकृत पशुओं के चयन में निहित नहीं है अभी तो उन्हें समस्त संवैधानिक ढांचे की समग्र रूपरेखा के अनुरूप बनाने में है हमारी संघीय व्यवस्था के विभिन्न रूप को बनाए रखने के लिए संघीय संत का प्रयोग जानबूझकर कहीं भी नहीं किया गया इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा संविधान यदि परंपरागत अर्थ में अपने प्रथम अनुच्छेद की विशेषता के कारण संघीय है जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा

डॉ अंबेडकर ने सभा में कहा हमारी संघीय व्यवस्था किसी कठोर सांचे में बंद नहीं है क्योंकि समय में परिस्थितियों को देखते हुए इसे संघात्मक में एकात्मक दोनों ही रूपों में रखा जा सकता है इसी तरह हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष से 1976 से 42 से संविधान संशोधन अधिनियम में इसको सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था मूल रूप में एक समाजवादी संघ की छाप का प्रयोग किए बिना जैसा इतने दृढ़ संतोष में आग्रह किया इसकी आधारभूत कसौटी समाजवादी रही जो स्थिति में निहित है एक तरफ में संपत्ति जैसे मूल अधिकार की व्यवस्था करता है तो दूसरी तरफ उसके साथ-साथ अधिकार को ऐसे प्रबंध में नियमों के अधीन रख दिया गया है जिन्हें राज जनता की भलाई में लगा सकता है

इस मिशन संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है क्योंकि इसमें सरकार की कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद को प्रदान की है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और जो समरूप रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है अंतिम यद्यपि हमारे यहां न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है तथापि अदालत को इस विषय का अधिकार से वंचित रखा गया है जिससे विधायक अधिनायक वाद स्थापित कर सके इस भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण समझ जाना चाहिए

विकल्पों की खोज की अनोखी समस्या के विचित्र समाधान के कारण ही भारतीय संविधान को विचारधारा की दृष्टि से एक निष्पक्ष दस्तावेज कहा जाता है हमारा संविधान उदारवाद से लेकर समाजवाद तक ही नहीं बल्कि साम्यवाद तक किसी भी विचारधारा की पूर्ति कर सकता है यह परिपूर्ण या एकाग्र रूप से किसी भी सिद्धांत का अर्थ पूरी तरह सिद्ध नहीं करता उदाहरण के लिए जब इनका तृतीय भाग मूल अधिकारों के प्रतिभूति करता है तो यह उन पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था द्वारा उनकी कटौती करने की अनुमति भी देता है एक सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण तत्वों को यह संविधान राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखता है

संपत्ति के मूल अधिकार का उदाहरण लेकर यह कहा जाता है की की मौलिक अधिकारों में एक अधिकार रहा है जो न्यायालय द्वारा मान्यवी रहा है यह उतना ही अमूल अधिकार भी रहा है क्योंकि संसद जनता के लिए के नाम पर इस अधिकार की कठोरता से कठोरती करती रही

13 दिसंबर 1949 ई को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लक्ष्य प्रस्ताव पेश किया उसमें निहित भावों के आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना तैयार प्रस्तुत और स्वीकृत की गई भारत के भावी संविधान की रूपरेखा के विषय में पंडित नेहरू ने गांधी जी द्वारा 1931 ईस्वी में दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए जाते समय व्यक्ति विचारों के आधार पर लक्ष्य प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत किया था गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान लाने का प्रदान करूंगा जो उसे गुलामी से मुक्त करें सभी अधिकार दिन ऐसी व्यवस्था करें इसमें 1920 का कोई अंतर ना हो सभी संप्रदाय के लोग मिलकर रहे छुआछूत का कोई स्थान ना हो नशीली मदिरा के लिए कोई स्थान ना हो शोषण ना हो तथा पूरे संसार के साथ शांतिपूर्ण संबंध को उनकी इन्हीं विचारों को आधार मानकर संविधान की प्रस्तावना तैयार और स्वीकृत की गई

अथवा

प्रश्न7.भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए

Ans.

संविधान सभा के लिए मांग की उत्पत्ति.

संविधान सभा का गठन तथा उसकी सदस्यता.

संविधान सभा का कार्य.

समितियां की नियुक्ति.

संविधान की प्रस्तावना.

भारतीय संविधान के स्रोत.

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं

1. विशाल एवं विस्तृत संविधान.

2. संपूर्ण प्रभु सट्टा संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य.

3. रूप में संघात्मक और आत्मा में एकात्मक संविधान.

4. संसदीय शासन व्यवस्था.

5 मौलिक अधिकार.

6. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत.

7. न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चिता.

8. न्यायिक पुन निरीक्षण.

9. धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य.

10. लचीला तथा कठोर संविधान.

11. प्रभु सट्टा जनता में निहित है.

12. एक लोकतांत्रिक गणतंत्र.

13. वयस्क मताधिकार.

14. एकल नागरिकता.

15. भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है.

प्रश्न 8. भारतीय देसी राज्यों का विलय एक रक्तहीन क्रांति थी व्याख्या कीजिए.

Ans. भारत सरकार की बनाई गई नीति के अनुसार उसे समय देसी नरेशों का आपस में मिलना निषेध था उन्हें अलग-अलग रखा जाता था विवाह आदि के मुंह को पर भी एक देसी नरेश को दूसरे से मिलने के लिए भारत सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती थी

मटफोर्ड के पश्चात इस नीति को छोड़ दिया गया अब प्रथम बार यह स्वीकार कर गया की देसी नरेशों के आपसी संबंधों में किसी प्रकार का खतरा नहीं था केवल इतना ही नहीं इस और अन्य बड़ा पग भी उठाया गया भारत सरकार ने देसी नरेशों के मंडल की स्थापना करने से किया

बटर कमेटी रिपोर्ट. देसी नरेशों के दिल में भारत सरकार की हस्तक्षेप की नीति के प्रति असंतोष था उनका कहना यह था कि वे स्वतंत्र थे और उन्होंने केवल विदेशी मामलों में कुछ विशेष स्थितियों में भारत सरकार के असर को स्वीकार किया था अव्यय संगठित हुए तो एक बार फिर उन्होंने देसी राज्यों की स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की देसी नरेशों को सर्वोच्च सट्टा का ब्रिटिश सिद्धांत बिल्कुल पसंद नहीं था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उन्होंने 15 स्वतंत्रता की मांग द्वारा ई भारत सरकार ने देसी निवेशों की सीमा को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया गवर्नर जनरल रीडिंग ने मार्च 1926 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम को लिखे पत्र में साफ-साफ कह दिया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी और किसी भी देसी निवेश को बराबरी का दवा नहीं करना चाहिए निजाम को लिखे गए इस पत्र से द्वारा यह प्रसिद्ध देसी नरेशों के सामने आया कि भारत सरकार सेउनके राजनीतिक संबंध किस प्रकार के थे उन्होंने मांग की की स्थिति को स्पष्ट किया गया जाए अधिकतर भारत सरकार ने पटना कमेटी को लूट लिया 1927 में की इस कमेटी का मुख्य काम था देसी राज्यों के साथ भारत सरकार के संबंधों पर विचार करना देसी नारियों के प्रसिद्ध वकीलों को ब्रिटेन से बुलाकर कमेटी के सम्मुख ने पक्ष को पेश किया उनका प्रमुख उत्तर यही था कि सर्वोच्च सत्ताधारी शक्ति के अधिकार सीमित थे यह कहा गया कि भारत सरकार को देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हर प्रकार से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था अब किंतु इस लंबी नदी से देसी निर्देशकों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ बटलर कमेटी ने सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत को फिर से व्याख्या करते हुए भारत सरकार को देसी राज्यों के प्रति हर प्रकार के अधिकार स्वीकार किया

कैबिनेट मिशन तथा देसी राज्य.

1940 ईस्वी में भारत में राजनीतिक पारिवारिक तेज गति से हो रहे थे दूसरी तरफ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली के भारतीयों को सट्टा जल्दी से जल्दी सल्तनत की घोषणा कर दी थी इस घोषणा से राजा अपनी संप्रभुता के लिए चिंतित थी तो मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान निर्माण के लिए दूसरी तरफ कांग्रेस भारत की अखंडता के लिए प्रयास कर रही थी इन कठिन हालातो के समाधान के लिए प्रधानमंत्री इटली में 10 फरवरी 1946 ई को भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की इसमें एथिक्स लॉरेंस तथा ए सी सिकंदर शामिल थे यह मिशन 24 मार्च को भारत पहुंचा उसने नरेंद्र मंडल के कुलपति मध्यकाल रियासतों के प्रतिनिधि पटियाला तथा बीकानेर और नवाब नगर के शासको से संयुक्त रूप से बातचीत की इसमें

छोटी रियासतों का प्रतिनिधित्व डूंगरपुर तथा बिलासपुर के राजा कर रहे थे सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद का प्रतिनिधित्व नवाब छतरी ने किया जबकि ट्रेवल का सर सीपी रामास्वामी अयर महाराज जयपुर का प्रतिनिधित्व विचार इस्माइल खान ने किया परंतु कैबिनेट मिशन ने उनके सामने यह घोषणा कर दी की एक नवीन शासन के स्थापित होते ही रियासतों पर कम की सर्वोच्च सट्टा का भी अंत हो जाएगा रावण के साथ अपने संबंधों पर आधारित रियासतों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे और रियासतों ने कम के सामने जिन अधिकारों को समाप्त कर दिया था वे उन्हें वापस मिल जाएंगे

भारत स्वतंत्रता अधिनियम विदेशी रियासतें.

भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया उसकी सातवीं धारा में देशी रियासतों के संबंध में निम्नलिखित उपबंध द 15 अगस्त 1947 ईस्वी में से भारतीय देशी रियासतों के राजाओं के ऊपर ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी अर्थात देसी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी और यह देसी राजा अपनी इच्छा से किसी भी उपनिवेशमें अपने संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे उनके राज्यों और अंग्रेजी प्रदेशों के बीच डॉक्टर का यातायात आदि के संबंध है यह पूर्ववर्ती बने रहेंगे जब तक कोई पक्ष उनको समाप्त करने का निर्णय दिया

सर्विसेज सट्टा की समाप्ति तथा देशी रियासत है.

भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत की देशी रियासतों को स्वतंत्र भी कर दिया और उन पर से अपनी सर्वोच्च सप्ताह उठा ली इसके साथ ही भी सारी संध्या भी समाप्त हो गई जो ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के साथ की थी इस अधिनियम ने इस समस्या के समाधान के बारे में कुछ भी नहीं लिखा त्रवंकोर हैदराबाद भोपाल और कई रियासतों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी इससे देश की एकता खत्म पड़ गई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत के इस बाल कनीकरण की निंदा की जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा की संप्रभुता राजाओं में नहीं जनता में निवास करती है

देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय.

रियासतों के भारत में विलय की जिस समस्या को लोन डेविल नहीं समझ सके थे इस गंभीर समस्या को लॉर्ड माउंटबेटन के चतुर्थसरदार पटेल की महान राजनीतिक गीता कभी कॉलेज पटियाला बडौदा ग्वालियर तथा जयपुर के नरेशों की देशभक्ति ने 2 मार्च के अंत काल में हल कर दिया समस्या की जटिलता को देखते हुए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यह इतने अल्प समय में सफलतापूर्वक हल कर ली जाएगी 1947 में ही सरदार पटेल ने यह भी घोषणा की सम्राट की सर्वोच्च सत्ता की अब मृत्यु हो गई है और उसे पर कोई आंसू नहीं बहता परंतु इसका अर्थ नहीं समझा जा सकता कि क्योंकि सर्वोच्च सट्टा का विलय हो गया

है भारत में सकता है कि नहीं भारतीय सरकार का एक सरकार के रूप में कार्य करना चाहती है और वह भारत के किसी भी भाग में आरक्षाक्त पलटने नहीं देख सकती पटेल की यह सूचना का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासत में भारत संघ में सम्मिलित हो गई **25** जुलाई **1947** को देश इतिहास में लेने लिया कि मैं प्रवेश पत्र के अनुसार भारतीय संघ में मिल जाना चाहिए इस महीने व्यवस्था थी कि जब तक भारत की संविधान सभा अपना संविधान भेसित रियासतों के **93** पैसे वीडियो के सहयोग से तब तक प्रतिरक्षा बाहरी मामले परिवहन और अन्य साहित्य विषयों के संबंध में मिलने वाली रियासतों के लिए कानून प्रभुत्व संसदीय बनाई थी

प्रश्न 9. भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है

Ans. आर्थिक नियोजन व्हाट्सएप में दो शब्दों से मिलकर बना है आर्थिक प्लस नियोजन आर्थिक का मतलब आर्थिक क्रियो से है और नियोजन का आज से भविष्य की कठिनाइयों की विरोध उचित प्रबंध करने से है इस प्रकार आर्थिक लक्षण को प्राप्त करने के लिए पहले से सुविचारित प्रबंध करना ही आर्थिक नियोजन है

1. **परिभाषा.** आर्थिक नियोजन से आज से एक संगठित के केआर्थिक पर्यटन से है जिसमें एक निश्चित एवं सुपारी भट सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण तरीके से समन्वय और नियंत्रण किया जाता है इसके सही अर्थ को गहराई से समझने के लिए निम्न परिभाषाओं को आधार बनाया जा सकता है

हेयक के अनुसार. आर्थिक नियोजन से अभिप्राय केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादन क्रियो के निर्देशन से है.

के के गुप्ता के अनुसार. आर्थिक नियोजन विकास का वह तरीका है जिसमें निश्चित लक्षणों को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रण एवं समन्वय द्वारा अल्प साधनों से न्यूनतम समय में पूरा किया जाता है सरकारी परीक्षण व अंतिम समीक्षा जिसका जरूरी अंग है

2. **लक्ष्मण या विशेषताएं.**

1. निश्चित उद्देश्य. आर्थिक नियोजन में प्रत्येक कार्य एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है लक्षण का निर्धारण करना नियोजन का एक प्रमुख भाग है रोजगार में वृद्धि करना आर्थिक स्थिरता लाना कृषि का विकास करना साधनों का उचित प्रयोग करना गरीबों और शिक्षा को दूर करना देश का सामाजिक कल्याण करना आदि नियोजन से के खास लक्षण है

2. समस्त आर्थिक कार्य योजना अनुसार. आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश में संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का संचालन पहले से बनाई गई योजना के अनुसार किया जाता है

3. साधनो की फुल जानकारी. आर्थिक नियोजन के लिए देश में उपलब्ध साधनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए वास्तविक तथा व्यावहारिक नियोजन तभी पूर्ण हो सकता है जबकि साधनों को पूर्ण जानकारी साधनों की सही जानकारी तभी हो सकती है जबकि व्यवस्थित समयक उपलब्ध हो

4. साधनों का विवेकपूर्ण वितरण. आर्थिक नियोजन में साधनों का वितरण एवं प्रयोग लक्षणों के बिना प्राथमिकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण नीति से किया जाता है अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन में साधनों का विवेकपूर्ण और अधिकतम उपयोग किया जाता है

5. राजकीय हस्तक्षेप. आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय नियंत्रण रहता है इसमें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कोई जगह नहीं होती देश में जो निजी उद्योग खोले जाते हैं उन्हें परन सरकारी निर्देशों को मानना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर सरकार स्वयं उद्योगों की स्थापना करती है

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

1. आर्थिक उद्देश्य. आर्थिक नियोजन के अंतर्गत समानता आर्थिक लक्षण का सबसे अधिक महत्व होता है वास्तव में आर्थिक उद्देश्यों में प्राप्त करने के लिए ही आर्थिक नियोजन का विकास किया जाएगा है आर्थिक नियोजन की कुछ आर्थिक लक्ष्य निम्न है

1. बहुत से देश में प्राकृतिक साधनों का तो बहुत होता है लेकिन वह उनका पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण निधन बने रहते हैं आज भारत की यह एक प्रमुख समस्या है नियोजन का लक्ष्य यह भी होता है कि देश में कवि का साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए ताकि आर्थिक विकास की गति में तेजी लाई जा सके

2. आय का आसमान वितरण.

3. प्रत्येक नागरिक को अवसर की सामान्य प्रदान करना.

4. लोगों के जीवन में वृद्धि.

5. भारत जैसे विकासशील देशों में पिछड़े क्षेत्र का विकास करना

6. तकनीकी विकास.

2. **सामाजिक उद्देश्य.**

1. समझने की पूरी मेहनत तथा लगन से कार्य करें.

2. आर्थिक नियोजन का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना भी है.

3. जनता की जीवन स्तर में सुधार हो.

4 समाज में रहने वाले व्यक्ति की नैतिक स्तर में वृद्धि

3. **राजनीतिक उद्देश्य.**

1. नियोजन का मुख्य लक्ष्य शांति स्थापित करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही संभव हो सकता है

2. विकसित देशों में सुरक्षात्मक लक्ष्य का विशेष महत्व रहता है क्योंकि यह राष्ट्रपति पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं तथा अपने देश में रक्षात्मक तैयारी करना भी जरूरी हो जाता है

3. कुछ देशों में आक्रामक कार्य हेतु भी नियोजन का बहुत महत्व रहता है इटली में पास शिफ्ट नियोजन का लक्ष्य रोमन साम्राज्य की स्थापना हेतु आधार तैयार करना था

4. देश के रीति रिवाज को किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है कि वायु पीढ़ी का स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर विकसित अवस्थाओं के अनुकूल हो सकती है

5. राजनीतिक लक्ष्य में राजनीतिक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं होता है

पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य.

गुलामी की वीडियो तोड़कर वर्ष 1947 ईस्वी में जब भारत कर स्वतंत्रता के स्वरूप द्वार पर खड़ा हुआ तो देश का आर्थिक विकास करने की दृष्टि से 1 अप्रैल 1951 उसी को देश का आर्थिक नियोजन शुरू किया गया तब से अब तक नियोजन के लगभग 65 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस अवधि में विभिन्न पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया यहां पर हम आरंभिक दिन पंचवर्षीय योजना का ही अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार से

1. आदित्य महल तथा देश विभाजन के कारण उत्पन्न आर्थिक संतुलन को दूर करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था

2. इस योजना के आरंभ से ही केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ परियोजना शुरू की गई थी इन परियोजना को भी पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया वास्तव में उन योजनाओं को पूर्ण करना प्रथम योजना का प्रमुख उद्देश्य था

3. इस योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास करना तथा राष्ट्रीय आय में जीवन स्तर में वृद्धि करना था

4. देश में उपलब्ध मानवीय में भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पैदा किया जा सके.

5. इस योजना का यह भी लक्ष्य था कि आज संपत्ति तथा अवसर की असमानता दूर हो

6. अधिकतम सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना भी प्रथम योजना का लक्ष्य था

7. इस योजना के खदान की कमी को देखते हुए कृषि उत्पादन वृद्धि करने को भी कुछ प्राथमिकता की गई थी

2. **द्वितीय पंचवर्षीय योजना. यह योजना 1 अप्रैल** 1956 से 31 मार्च 1961 तक के लिए थी.

1 इस योजना का राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के उद्देश्य रखा गया था ताकि जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके इस दृष्टि से राष्ट्रीय आय में 5 वर्षों में से 25% वृद्धि का उद्देश्य रखा गया था

2. इस योजना का बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रोजगार के मौका में वृद्धि करना भी एक प्रमुख लक्ष्य था योजना अवधि में 105 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार दिलाने का लक्ष्य निश्चित किया गया

3. इस योजना में इस्पात रसायन विद्युत तथा अन्य आधारभूत उद्योगो का विस्तार करना तथा मशीन निर्माण उद्योगों की स्थापना करना जिससे 10 वर्ष के अंदर औद्योगीकरण की समस्त ज़रूरतें पूरी हो सके

4. देश में आए हुए संपत्ति एवं आय की असमानताओं में कब मिलना तथा आर्थिक शक्ति में केंद्रीकरण को कम करने के तथा उसका नियोजित वितरण करना भी इस योजना का उद्देश्य था

3. **तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 66.**

1. राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक की दर से वृद्धि करना तथा विनियोजन इस प्रकार करना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का क्रम आगामी योजनाओं तक चला रहे

2. यह लक्ष्य रखा गया कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाएगा और अन्य कृषि उत्पादों में कितने वृद्धि की जाएगी की घरेलू उद्योगों और निर्यात की जरूरत को पूरा किया जा सके

3. आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देकर अगले दशक तक एक मजबूत औद्योगिक आधार तैयार करना एवं आर्थिक संरचना का निर्माण करना

4. देश में उपलब्ध जनशक्ति का पूर्ण उपयोग और रोजगार के साधन वृद्धि करना

5. नौकरी की समानता की अधिकतर अधिक स्थापना करना की असमानता में कमी लाना एवं आर्थिक शक्ति के वितरण में समानता लाना ।

प्रश्न 10. भारत की विदेश नीति के निर्माणत्मक तत्वों की विवेचना कीजिए

Ans. भारत की विदेश नीति के निर्माण आत्मक तत्व.

1. **राष्ट्रीय हित -**

2. भौगोलिक तत्व। -

3. गुटबांदीयां। -

4. विचारधाराओं का असर

5. आर्थिक तत्व। -

6. सैनिक तत्व। -

7. पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तितत्व। -

8. ऐतिहासिक परंपराएं। -

9. आंतरिक शक्तियों और दावों का प्रभाव। -

प्रश्न 11. भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए

Ans. अंतरिक्ष सरकार की सितंबर 1946 में स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी पंडित नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगी और वह किसी गुप्त में शामिल नहीं होगा भारत उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करेगा और विश्व शांति के समर्थक देश का साथ देगा जो राष्ट्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष करेंगे भारत उनका सहयोग करेगा यही विचार भारत की विदेश नीति का आधार बने भारत की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है

1. गुटनिरपेक्षता

2. मैत्री और से अस्तित्व की नीति

3. विरोधी कुत्तों के बीच सेतु बांध बनाने की नीति

4. साधनों की पवित्रता की नीति

5. साम्राज्यवाद और प्रजाति विभेद का विरोध

6. संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति

7. अफ़रसीआई एकता

प्रश्न 12. गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक निबंध लिखिए

Ans द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व दो शक्तिशाली कुत्तों में अमेरिका और सोवियत संघ में विभक्त हो गया वहीं पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा तीसरी दुनिया का उदय हुआ इस आंदोलन का उद्देश्य

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा युद्ध को रोकना था यह आंदोलन अत्यधिक शक्तिशाली था जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तथा शीत युद्ध के विरुद्ध चलाया गया था

तीसरी दुनिया में ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नवोदय देश की बढ़ती हुई भूमिका तथा उपनिवेशवाद के अंत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था मिश्रा अफ्रीका जैसे देशों ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की के देश साम्यवादी अच्छा तथा पूंजीगत वोटो से अलग थे इन अच्छा निरपेक्ष देशों को तृतीय विश्व कहा गया

तीसरी दुनिया एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन. भारत मिश्रा अफ्रीका जैसे देशों के लिए तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया था इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में फ्रांस के जनसंख्या विशेषज्ञ अल्फ्रेड सेवी ने किया था एक लंबी गुलामी से मुक्ति मिलने के पश्चात अब यह राष्ट्र अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करना चाहते थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसकी स्थापना की योजना के अक्सर अवसर पर 7 सितंबर 1946 को बनाई गई 1947 ईस्वी में भारत ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें एशियाई देशों की स्वतंत्रता की मांग की गई थी भारत में चीन के विचारों में मतभेद था परंतु फिर भी यह दोनों देश पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को स्वीकारना नहीं चाहते थे इसी कारण गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में वृद्धि होती गई 1961 ईस्वी में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 113 देशों ने भाग लिया था आज इसके सदस्य देशों की संख्या 115 तक पहुंच चुकी है तीसरी दुनिया को शक्तिशाली बनाने में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मिश्रा के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री मार्शल टीटो ने महत्वपूर्ण भूमिका **निभाई**

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता. 1947 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उत्थान हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत मिश्र अफ्रीका युगोस्लाविया आदि अनेक देशों द्वारा चलाया गया गुटनिरपेक्ष देशों ने अन्य देशों को गुटनिरपेक्षता की सदस्यता प्रदान करने के लिए 1961 ईस्वी में पंचशील सिद्धांत बनाया अर्थात पांच सत्य निश्चित की जो इस प्रकार है

1. यह है वह देश स्वतंत्र नीति का पालन करता हो 2. सदस्य बनने वाला देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता हूं

3. वह शीत युद्ध के संबंध में किसी भी सैनिक गुटखा सैनिक संधि का सदस्य हो

4. उसने किसी भी देश या महाशक्ति के साथ विपक्षीय सैनिक संधि ने की हो

5. उसने किसी भी महाशक्ति को अपनी सीमा में सैनिक या हवाई अड्डे बनाने की अनुमति ने प्रदान की हूं

गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास

1. पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बिल ग्रेट 1961.

2. द्वितीय निर्गुण सम्मेलन काहीरा 1964.

3. तीसरा निर्गुण शिखर सम्मेलन लूसका 1970.

4.चौथा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन अल्जीयर्स 1973.

5. पांचवा निर्गुण शिखर सम्मेलन कोलंबो 1976.

6. छोटा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हवाना 1979.

7. सातवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1983.

8. आठवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हरारे 1986.

9. नोवा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड 1989.

10. दसवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जकार्ता 1992.

11. 11वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कार्ड जाना 1995.

12 गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन डरवान 1998.

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण शीत युद्ध था यह आंदोलन 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू करनाल नासिर कथा मार्शल टीटो ने युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में शुरू किया था यह आंदोलन राजनीतिक प्रकृति का था तथा उसने आर्थिक विकास पर बोल दिया था शीत युद्ध के समाप्त होने का असर इस आंदोलन पर भी पड़ा परंतु शीत युद्ध के पुण्य शुरू होने से इस आंदोलन की भी नई शुरुआत हुई इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या निरंतर बढ़ती गई 1985 ईस्वी में गोरवा से रूस के सर्वोच्च नेता बने उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में ग्लास नोट तथा स्ट्राइक का नामक सुधार किया इसके परिणाम स्वरुप शीत युद्ध समाप्त हो गया और अधिकांश देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समाप्ति की मांग की

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना.